नए उभरते भारत की परिकल्पना

–प्रो. सुमन पामेचा, मीनाक्षी अहीर

अगर यह कहा जाए कि गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उज्ज्वला योजना ने जहां करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है वहीं स्वच्छ भारत अभियान से देशभर में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और खुले में शौच जाने के मामलों में काफी कमी आई है। यही नहीं जन–धन योजना ने करोड़ों ग्रामीण के बैंक खाते खोल सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाने की सुविधा प्रदान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। ऐसी ही कई योजनाओं से आज देश उन्नति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है और नए भारत की परिकल्पना मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। इस मार्ग में कई चुनौतियां और बाधाएं भी हैं। सही रणनीति से इन बाधाओं को पार करने की जरूरत है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अपनी प्रगति तथा आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के लिए काफी प्रयास किए। तथा उसके लिए समय–समय पर कई नई योजनाएं तथा नीतियों का निर्माण किया गया जिनके माध्यम से आज देश सभी क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है जैसे विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार एवं स्वास्थ्य आदि।

इसके बावजूद आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी काफी सारी असंतोषजनक स्थितियां अभी तक भी हमारे बीच बनी हुई हैं जिसके कारण देश को प्रगति पथ पर चलने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय समावेशन के जरिए सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यापार रोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी को शिक्षा, महिला सुरक्षा, पोषण आदि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनडीए सरकार कई नई योजनाएं लाई। या फिर पहले से चल रही योजनाओं की कमियों को दूर कर उन्हें नया रूप–रंग दिया गया। इस लेख में ऐसी ही कुछ नवीन एवं लोकप्रिय योजनाओं का वर्णन किया गया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

वित्तीय समावेशन के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग 60 प्रतिशत बैंक खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए (अप्रैल 17 तक)। इसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना एक बैंक अकाउंट बनाना होगा जिसमें उन्हें एक लाख रुपये की बीमा राशि एवं डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। यह योजना गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिससे व्यक्तियों में बचत की भावना का विकास हो; साथ ही अपने भविष्य की सुरक्षा का अहम भाव जागे। इसके अलावा, इस कदम से देश का पैसा भी सुरक्षित होगा और जनहित के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत गरीबों को बैंकों में मुफ्त में खाता खोलने का मौका दिया गया। इस योजना के जरिए करीब 29 करोड़ नए खाताधारक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। **यह योजना जहां गरीबों को सशक्त करने का काम कर रही है वहीं इसके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के चलते भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े रास्ते को सरकार ने हमेशा–हमेशा के लिए बंद कर दिया है।** इन खातों में अप्रैल 2017 तक लगभग 65 हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके थे।

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2014 को की गई। यह योजना भारत में निवेश के लिए

जनधन खाते 2017 (करोड़ में)

वर्ष	जन–धन खाते	जीरो बेलेंस खाते
2014	10	18
2015	20	25
2016	25	30
2017	30	70

स्रोत– वित्तीय सेवा विभाग, सर्वेक्षण परिकलन

सारणी में स्पष्ट है कि 2014 में जनधन खाते 10 करोड़ तथा जीरो बेलेंस खाते 18 करोड़ थे; 2017 तक बढ़कर जनधन खाते 30 करोड़ व जीरो बेलेंस खाते 70 करोड़ तक हो गए हैं।

(राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय) पूरे विश्व में से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को बुलाने के लिए किया गया एक प्रयास है जो देश के सभी क्षेत्रों में (उत्पादन, टेक्सटाईल्स, आटोमोबाइल्स, रसायन, आईटी, बंदरगाह, औषधि तथा रेलवे, चमड़ा आदि) अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए दिया गया अवसर था। यह योजना व्यापार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने, डिजिटल नेटवर्क के बाजार में सुधार के साथ ही असरदार भौतिक संरचना के निर्माण पर केंद्रित है।

इसका प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया हुआ एक विशाल शेर है जिसके पास ढ़ेर सारे पहिए है जो शंतिपूर्ण प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के रास्ते को इंगित करता है। कई पहियों के साथ चलता हुआ शेर हिम्मत, मजबूती, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रकों में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का ध्यान बड़ी संख्या में मूल्यवान और सम्मानित नौकरी के अवसर पैदा करना है।

इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट और रहने योग्य घर बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख निवेशकों की मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के 25 क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष 74 प्रतिशत, रक्षा 49 प्रतिशत, समाचार मीडिया 26 प्रतिशत को छोड़कर 100 प्रतिशत एफ.डी. आई. की अनुमति हुई है। जापान व भारत ने 12 बिलियन डॉलर जापान–भारत मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस सुविधा निधि की घोषणा की।

भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए 2015 में विश्व–स्तर पर उभरा है तथा वर्ष 2016–17 में भारत को 60 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ भारत अभियान

यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय–स्तर के इस अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों, शहरों, नगरों, गांवों, कस्बों आदि को साफ–सुथरा करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना उन्हें समर्पित की गई।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में ग्रामीण स्वच्छता दायरा

वर्ष	स्वच्छता दायरा (प्रतिशत में)
1981	9
1991	22
2001	32
2011	39
2018	76

स्रोत– स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय (10.01.2018 के अनुसार)

स्वच्छ भारत योजना में कलस्टर एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को धीरे–धीरे समाप्त करना है। यह मिशन शौचालयों के उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की एक पहल करेगा।

सरकार ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

मई 2018 तक 296 जिलों व 307349 गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से देश के अंतर्गत स्वच्छता का दायरा बढ़ता जा रहा है। 1981 में 9 प्रतिशत था जो इस अभियान के चलते 2018 तक 76 प्रतिशत हो गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ मुद्रा योजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस भारी–भरकम कोष के साथ 3,000 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी जोड़ा गया है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया योजना लागू करने के बाद सरकार ने उसमें कारोबार और रोजगार की भावना को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहयोग हेतु इस योजना को शुरू किया।

इस योजना के माध्यम से सरकार ने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों और लघु व्यवसायों को सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही कोई नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।

मुद्रा बैंक ने ऋण को तीन वर्गों में बांटा है–

1. शिशु ऋण– 50,000 रुपये तक का ऋण
2. किशोर ऋण – 50,000 से 5 लाख तक
3. तरुण ऋण – 5 लाख से 10 लाख तक

इस योजना के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राशि लोगों को जारी भी हो चुकी है। वैसे मुद्रा योजना से 7.45 करोड़ उद्यमी लाभ उठा चुके हैं। 3.17 लाख करोड़ रुपये ऋण के तौर पर दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की इकाइयों को वितरित ऋण (करोड़ में)

इकाइयों का वर्ग	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	खातों की संख्या	वितरित ऋण	खातों की संख्या	वितरित ऋण
शिशु ऋण	324.1	62027.69	364.98	83891.88
किशोर ऋण	20.60	41073.28	26.64	51063.12
तरुण ऋण	4.10	20853.73	5.40	40357013
योग	**34.88**	**132954.73**	**397.02**	**175312.13**

स्रोत– बैंकिंग सेक्टर एवं विभाग

अटल पेंशन योजना

यह योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी। पहले की 'स्वावलंबन' योजना में मौजूद त्रुटियों को खत्म कर उसको नवीनीकृत कर अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। जो ग्राहक 'स्वावलंबन' से जुड़े थे, उन सभी को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा "दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तब उसके पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। इसलिए जन–धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है।"

इस योजना के शुरू होने से किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना को प्रभावी बनाया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। अटल पेंशन योजना के द्वारा 2017 तक 84 लाख से अधिक ग्राहक 3194 करोड़ रुपये से अधिक परिसंपत्ति के साथ पंजीकृत हैं।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 से शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल क्षेत्र में सशक्त समाज और ज्ञान को बढ़ाना है। इस योजना के द्वारा भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सहयोग से भविष्य के भारत को सशक्त और ज्ञान–संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल इंडिया का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है–

1. हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा;
2. मांग पर संचालन एवं सेवाएं;
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

लक्ष्य

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे की उपलब्धि
- नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक हाईस्पीड इंटरनेट
- डिजिटल पहचान अंकित करने का अनोखा स्थान
- मोबाईल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिको की भागीदारी हो
- पब्लिक स्थान पर सुरक्षित साइबर कैफे

डिजिटल इंडिया के कार्यक्षेत्र

1. ब्रॉडबैंड हाइवेज, 2. मोबाइल कनेक्टिविटी
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
4. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
5. रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

देश के प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित ब्लॉकों के प्रत्येक पात्रधारी परिवार के एक सदस्य का चुनाव करते हुए 10 लाख लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से शुरू किया गया। इस योजना की रूपरेखा गिरते शिशु लिंगानुपात के समाधान के लिए बनाई गई है। यह योजना शुरुआत में 100 जिलों में लागू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव विकास मंत्रालय की एक त्रि–स्तरीय पहल है।

19 अप्रैल, 2016 को यह योजना 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 61 अतिरिक्त जिलों में चलाई गई। इस योजना की उपलब्धि के तौर पर पहले साल में जन्म के समय लिंगानुपात में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। अभी के वर्षों में लिंगानुपात में न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य है तथा आगामी पांच सालों में धीरे–धीरे इसे और अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में अन्य कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं:–

- बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी
- 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव
- हर गांव में गुड्डा–गुड़िया बोर्ड का गठन
- लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा
- लड़कियों के लिए स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था भी शामिल है।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला–स्तरों के सम्मिलित प्रयास से 100 जिलों से प्राप्त आंकड़ों की प्राथमिक रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान अप्रैल–मार्च के मध्य बीबीबीपी स्कीम वाले 58 प्रतिशत जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात दर में वृद्धि दिखाई गई हैं। 69 जिलों में प्रसवपूर्ण देखभाल वाले मामलों में प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण मे वृद्धि देखी गई हैं।

मंत्रालय द्वारा 2017 में राजस्थान को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

स्टार्टअप इंडिया

16 जनवरी 2016 से लागू हुई स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि नए छोटे/बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें ऋण सुविधा, उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण आदि शामिल किया गया है। इसके तहत जरूरी स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

स्टार्टअप योजना पर नई नीति लागू होने के बाद हजारों करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। मुख्य बात यह है कि इसमें महिलाओं की भी जबर्दस्त भागीदारी है। इससे 2020 तक करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। 10 हजार करोड़ रुपये के कोष से शुरू हुआ स्टार्टअप अब लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। अब तक 800 स्टार्टअप का पंजीकरण हुआ है।

इस योजना के बनने से भारत के अनेक राज्यों ने अपने–अपने राज्य में कई नए कार्य किए हैं। केरल में केरल आईटी मिशन नामक एक सरकारी स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई जो राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश के लिए 50 अरब डॉलर लाने पर केंद्रित है। तेलंगाना ने भारत में सबसे बड़ा उष्मायत केंद्र ''टी हब'' के रूप में शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने 200 करोड़ रुपये के फंड बनाने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। राजस्थान में स्टार्टअप ओएसीस योजना शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही सफल और लोकप्रिय साबित हो रही है। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को केंद्र सरकार की और से निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था है।

इस योजना के तहत 2016 से 2019 तक कुल 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने हैं ताकि माताओं और बहनों के सेहत की सुरक्षा की जा सके। अब तक इस योजना के तहत 2.20 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

सरकार की अकेली उज्ज्वला योजना ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं का अब जीवन के प्रति नजरिया ही बदल कर रख दिया है। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का काम किया है। इस योजना के द्वारा सरकार इस बात पर दूरदृष्टि कायम कर रही है कि अगर देश की महिलाएं व बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत भी सेहतमंद होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में राज्य सरकारों के साथ मिलकर 40 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों पर काम कर रहा है और इसमें 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। आने वाले कल में 8 से10 करोड़ महिलाओं को आजीविका के इस काम से जोड़ा जाएगा । 2014 से अब तक 5 लाख 70 हजार युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इनमें से तीन लाख अड़तालीस हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इसी प्रकार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 10 लाख 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और इनमें से 5 लाख 92 हजार को नौकरी उपलब्ध कराई गई ।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं से देश के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। देखा जाए तो भारत तकनीकी शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा तथा महिलाओं के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुए माना जाता रहा है पर इन विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत चलाई गई योजनाओं के परिणामस्वरूप देश प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

उज्जवला योजना के द्वारा हर घर के अंदर गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान से देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा खुले में शौच जाने आदि में कमी आना; बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देना ताकि व्यापार व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके; प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत घर की जरूरत की पूर्ति करना तथा अटल पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गों के लिए पेंशन की सुविधा देना ताकि वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी पर निर्भर ना रहे तथा वह इस पेंशन की राशि को अपने कमजोर स्वास्थ्य व भोजन पर व्यय कर सकें।

तकनीकी क्षेत्र में जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना व मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वह विदेश जाकर नौकरी ना कर अपनी खुद की पहचान के साथ देश को आगे बढ़ाएं।

यह सभी योजनाएं काफी हद तक सफल हो रही हैं तथा इन सभी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है। पर कभी–कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई नई योजना या कार्यक्रम बनता है तो वह पूरी तरह से आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है या ऐसा कहे कि जिन व्यक्ति को ज्यादा जरूरत हो वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योजना के विस्तार कार्यक्रम में दूरदराज के क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।

इन योजनाओं के बारे में गांव या पंचायत–स्तर पर जनता के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को जागरूक होने की जरूरत है ताकि वह इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यमों से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके।

(डॉ. सुमन पामेचा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर एवं मीनाक्षी अहीर शोधार्थी हैं।)

ई–मेल : sahir8086@gmail.com